YOJANASEWA.COM

https://yojanasewa.com

क्या फडणवीस छोड़ेंगे CM की कुर्सी? संजय राउत के दावे से हड़कंप

विषय सूची (Table of Contents):

>> १. महाराष्ट्र में सियासी हलचल क्या सीएम की कुर्सी छोड़ दिल्ली जाएंगे देवेंद्र फ...
>> दिल्ली में बड़ी जिम्मेदारी की अटकलें...
>> क्या महाराष्ट्र की कमान छोड़ना फडणवीस की मजबूरी है?...
>> २. संजय राउत का बड़ा दावा राज्य मंत्रिमंडल में फेरबदल और बीजेपी के नए मुख्यमंत्...
>> महाराष्ट्र को मिलेगा नया मुख्यमंत्री चेहरा?...
>> मंत्रिमंडल विस्तार और क्षेत्रीय समीकरण...
>> ३. अयोध्या राम मंदिर विवाद नागपुर में शिवसेना (उबाठा) का विशाल राम रक्षा आंदोल...
>> नागपुर में १८ जुलाई को बड़ा प्रदर्शन...
>> विदर्भ क्षेत्र के ११ जिलों से जुटेंगे रामभक्त...
>> ४. आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और बीजेपी नेताओं को आंदोलन में शामिल होने का खुला न्...
>> मोहन भागवत से विशेष अनुरोध...
>> बीजेपी विधायकों और स्थानीय नेताओं को निमंत्रण...
>> ५. लोकसभा परिसीमन का मुद्दा मल्लिकार्जुन खरगे की सर्वदलीय बैठक की मांग का राउत ...
>> संजय राउत ने जताई खरगे के रुख से सहमति...
>> क्यों महत्वपूर्ण है परिसीमन का मुद्दा?...
>> ६. मानसून सत्र में 131वां संशोधन 850 लोकसभा सीटों के प्रस्ताव पर क्या है विपक्ष...
>> लोकसभा सीटों की संख्या बढ़कर होगी ८५०...
>> विपक्ष की काउंटर रणनीति...
>> ७. सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का समर्थन परीक्षा में धांधली को लेकर केंद्र सरकार...
>> जंतर-मंतर पर २० साल की युवती का उपवास...
>> सत्ता में बैठे लोगों की संवेदना खत्म हो चुकी है ...
>> निष्कर्ष (Conclusion)...
>> जनता के सवाल (FAQs)...

Latest Update 2026:महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ा सियासी भूचाल आने के संकेत मिल रहे हैं। शिवसेना (उबाठा) के फायरब्रांड नेता और सांसद संजय राउत ने एक ऐसा दावा किया है जिसने राज्य से लेकर दिल्ली तक के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। इस नए राजनीतिक घटनाक्रम ने महाराष्ट्र के सत्ता समीकरणों को लेकर कई तरह के कयासों को जन्म दे दिया है।

यह पूरी बहस आगामी महीनों में होने वाले संभावित मंत्रिमंडल फेरबदल और संसद के मानसून सत्र से ठीक पहले शुरू हुई है। संजय राउत के इस बयान के बाद जनता और राजनीतिक विश्लेषक दोनों ही इस स्थिति (status) का आकलन करने में जुट गए

हैं। आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं।

१. महाराष्ट्र में सियासी हलचल: क्या सीएम की कुर्सी छोड़ दिल्

महाराष्ट्र के राजनीतिक हलकों में इस समय सबसे बड़ा सवाल यही तैर रहा है कि क्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की भूमिका बदलने वाली है? संजय राउत के हालिया बयान ने इस चर्चा को हवा दी है कि फडणवीस को राज्य की राजनीति से हटाकर केंद्र में भेजा जा सकता है।

दिल्ली में बड़ी जिम्मेदारी की अटकलें

राउत का मानना है कि यदि आगामी दिनों में केंद्र सरकार के स्तर पर कोई बड़ा निर्णय लिया जाता है, तो देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली बुलाया जा सकता है। उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर किसी महत्वपूर्ण मंत्रालय का जिम्मा सौंपा जा सकता है। इस बदलाव से महाराष्ट्र की सत्ता संरचना पर सीधा असर पड़ेगा।

क्या महाराष्ट्र की कमान छोड़ना फडणवीस की मजबूरी है?

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, बीजेपी आलाकमान समय-समय पर अपने राज्यों के नेतृत्व में बदलाव करता रहता है। हालांकि, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा हैं, इसलिए उन्हें दिल्ली भेजने के पीछे कोई बड़ी रणनीतिक योजना हो सकती है। आप इस राजनीतिक बदलाव की पूरी सूची (list) और अपडेट्स ऑनलाइन चेक (check) कर सकते हैं।

२. संजय राउत का बड़ा दावा: राज्य मंत्रिमंडल में फेरबदल और बी

शिवसेना (उबाठा) नेता संजय राउत ने नागपुर दौरे के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए एक बड़ा दावा किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगले एक से दो महीनों के भीतर केंद्र और महाराष्ट्र दोनों ही जगह मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है।

महाराष्ट्र को मिलेगा नया मुख्यमंत्री चेहरा?

संजय राउत के मुताबिक, यदि फडणवीस केंद्र में जाते हैं, तो महाराष्ट्र की गद्दी खाली होगी। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता

पार्टी (बीजेपी) के ही किसी अन्य वरिष्ठ मंत्री को महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। राउत का यह दावा राज्य की सत्ताधारी महायुति गठबंधन के भीतर भी खलबली मचा रहा है। इस संबंध में अन्य सामाजिक व धार्मिक गतिविधियों की जानकारी के लिए आपसर्व समाज उत्थान एवं विकास समिति का हवन संपन्न, 11का विवरण भी पढ़ सकते हैं।

मंत्रिमंडल विस्तार और क्षेत्रीय समीकरण

अगर यह फेरबदल होता है, तो केवल मुख्यमंत्री की कुर्सी ही नहीं, बल्कि कई अन्य मंत्रियों के विभागों में भी भारी बदलाव होगा। बीजेपी इस बदलाव के जरिए आगामी चुनावों के लिए नए क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश कर सकती है। इस बड़े बदलाव का लेटेस्ट अपडेट (latest update) जल्द ही आधिकारिक तौर पर सामने आ सकता है।

३. अयोध्या राम मंदिर विवाद: नागपुर में शिवसेना (उबाठा) का वि

राजनीतिक उठापटक के बीच, शिवसेना (उबाठा) ने एक नए मोर्चे पर आक्रामक रुख अपना लिया है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी ने अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और वित्तीय अनियमितताओं के खिलाफ एक बड़े प्रदर्शन की घोषणा की है।

नागपुर में १८ जुलाई को बड़ा प्रदर्शन

शिवसेना (उबाठा) द्वारा १८ जुलाई को नागपुर की धरती पर राम रक्षा आंदोलन आयोजित किया जा रहा है। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य राम मंदिर के प्रबंधन में पारदर्शिता की मांग करना और कथित घोटाले का विरोध करना है।

विदर्भ क्षेत्र के ११ जिलों से जुटेंगे रामभक्त

संजय राउत ने जानकारी दी है कि इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए विदर्भ क्षेत्र के सभी ११ जिलों से भारी संख्या में शिवसैनिक और रामभक्त नागपुर पहुंच रहे हैं। पार्टी इस आंदोलन के जरिए खुद को असली हिंदुत्ववादी साबित करने की कोशिश में है। राजनीति के साथ-साथ देश की अन्य बड़ी खबरों जैसे खेल जगत मेंविराट के मुरीद हुए जोकोविचकी कहानी भी काफी ट्रेंड कर रही है।

४. आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और बीजेपी नेताओं को आंदोलन में श

इस राम रक्षा आंदोलन को लेकर संजय राउत ने एक बड़ा दांव खेला है। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और बीजेपी समेत तमाम हिंदुत्ववादी संगठनों को इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए खुला निमंत्रण भेजा है।

मोहन भागवत से विशेष अनुरोध

राउत ने कहा, हमने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से व्यक्तिगत रूप से अनुरोध किया है कि वे इस आंदोलन में आएं। यदि उनके लिए स्वयं आना संभव न हो, तो वे संघ के किसी वरिष्ठ प्रतिनिधि को जरूर भेजें।

बीजेपी विधायकों और स्थानीय नेताओं को निमंत्रण

>> नागपुर और विदर्भ के सभी स्थानीय बीजेपी विधायकों को आमंत्रण पत्र भेजा गया है।

>> विभिन्न दक्षिणपंथी और हिंदुत्ववादी संगठनों को भी पत्र लिखकर समर्थन मांगा गया है।

>> संजय राउत का कहना है कि जो भी भगवान राम का सच्चा भक्त है, उसे इस चढ़ावा चोरी के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए।

५. लोकसभा परिसीमन का मुद्दा: मल्लिकार्जुन खरगे की सर्वदलीय ब

महाराष्ट्र की राजनीति से अलग, राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विपक्ष पूरी तरह से एकजुट नजर आ रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने संसद सत्र शुरू होने से पहले परिसीमन के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है।

संजय राउत ने जताई खरगे के रुख से सहमति

जब पत्रकारों ने नागपुर में राउत से इस बारे में पूछा, तो उन्होंने बिना किसी झिझक के कहा, हम मल्लिकार्जुन खरगे की बात से पूरी तरह सहमत हैं। विपक्ष का मानना है कि इतने बड़े और संवेदनशील मुद्दे पर सरकार को एकतरफा फैसला लेने के बजाय सभी दलों को विश्वास में लेना चाहिए।

क्यों महत्वपूर्ण है परिसीमन का मुद्दा?

परिसीमन के जरिए देश भर में लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जाना है। विपक्ष को डर है कि इस प्रक्रिया से कुछ राज्यों को नुकसान हो सकता है, इसलिए वे पहले ही इस प्रक्रिया को ऑनलाइन चेक (check) करने और इस पर आम सहमति बनाने के लिए दबाव डाल रहे हैं। ऐतिहासिक महत्व के विषयों जैसेबाल दिवस क्यों मनाया जाता है 14 नवंबर को?की तरह ही हमारे लोकतांत्रिक अधिकार भी बेहद महत्वपूर्ण हैं।

६. मानसून सत्र में 131वां संशोधन: 850 लोकसभा सीटों के प्रस्ताव

संसद का आगामी मानसून सत्र २० जुलाई से शुरू होने जा रहा है। सरकार इस सत्र में बेहद महत्वपूर्ण संविधान (131वां संशोधन) विधेयक लाने की पूरी तैयारी में है। इस विधेयक के प्रावधानों को लेकर राजनीतिक गलियारों में भारी सरगर्मी है।

लोकसभा सीटों की संख्या बढ़कर होगी ८५०

इस नए संशोधन विधेयक के तहत देश में लोकसभा सीटों की कुल संख्या को बढ़ाकर ८५० करने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही देश में नए सिरे से परिसीमन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यह भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास का एक बहुत बड़ा बदलाव साबित होने वाला है।

विपक्ष की काउंटर रणनीति

विपक्षी गठबंधन इस विधेयक के मसौदे को लेकर सतर्क है। सूत्रों के मुताबिक, विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए पूरी गाइडलाइंस और ड्राफ्ट पीडीएफ (PDF) का अध्ययन कर रहा है। विपक्ष का मुख्य एजेंडा यह सुनिश्चित करना है कि दक्षिण भारतीय राज्यों की सीटों के प्रतिनिधित्व में कोई कमी न आए। आप सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसके लिए कैसे अप्लाई ऑनलाइन (apply online) या संशोधन के नियमों को देख सकते हैं।

७. सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का समर्थन: परीक्षा में धांधली

दिल्ली के जंतर-मंतर पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई कथित अनियमितताओं और धांधली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। इस आंदोलन के समर्थन में प्रसिद्ध जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं, जिसका संजय राउत ने पुरजोर समर्थन किया है।

जंतर-मंतर पर २० साल की युवती का उपवास

संजय राउत ने केंद्र सरकार की संवेदनशीलता पर सवाल उठाते हुए कहा कि वहां एक २० साल की युवा लड़की भी देश के छात्रों के भविष्य के लिए अनशन पर बैठी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं की चीखें सुनने में नाकाम रही है।

सत्ता में बैठे लोगों की संवेदना खत्म हो चुकी है

राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर निशाना साधते हुए कहा, क्या इन आंदोलनकारियों की बिगड़ती तबीयत की रिपोर्ट शीर्ष नेतृत्व तक नहीं पहुंच रही है? मोदी मंत्रिमंडल के किसी भी मंत्री में इतनी हिम्मत नहीं है कि वे आगे आकर सोनम वांगचुक और देश के छात्रों के हक में खड़े हो सकें।

निष्कर्ष (Conclusion)

साल 2026 का यह समय भारतीय राजनीति के लिए बेहद संवेदनशील और बदलावों से भरा नजर आ रहा है। एक तरफ जहां महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली भेजे जाने और नया सीएम चेहरा लाने के दावों से सियासी पारा चढ़ गया है, वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर आंदोलन, परिसीमन विवाद और छात्रों के मुद्दों ने केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आने वाले मानसून सत्र में इन सभी मुद्दों पर तीखी बहस होना तय है। जनता को इन सभी बड़े बदलावों और आधिकारिक घोषणाओं की स्थिति (status) जानने के लिए आगामी कुछ हफ्तों का इंतजार करना होगा।

जनता के सवाल (FAQs)

शिवसेना (उबाठा) नेता संजय राउत ने दावा किया है कि आगामी मंत्रिमंडल फेरबदल में देवेंद्र फडणवीस को केंद्र में भेजा जा सकता है, हालांकि बीजेपी की तरफ से इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

यह आंदोलन १८ जुलाई को महाराष्ट्र के नागपुर शहर में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें विदर्भ के ११ जिलों के कार्यकर्ता भाग लेंगे।

उद्धव ठाकरे गुट का आरोप है कि अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी और वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं, जिसके विरोध में यह प्रदर्शन किया जा रहा है।

संजय राउत ने मोहन भागवत और संघ के अन्य नेताओं को खुला निमंत्रण भेजा है और उनसे स्वयं या अपना प्रतिनिधि भेजने का अनुरोध किया है।

इस विधेयक के तहत भारत में लोकसभा सीटों की संख्या को बढ़ाकर ८५० करने और नए सिरे से देशव्यापी परिसीमन प्रक्रिया शुरू करने का प्रस्ताव है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले परिसीमन के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है।

सोनम वांगचुक विभिन्न राष्ट्रीय परीक्षाओं में हुई कथित अनियमितताओं, पेपर लीक और धांधली के खिलाफ छात्रों के आंदोलन के समर्थन में अनशन पर बैठे हैं।

विपक्ष पूरी तरह विरोध में नहीं है, लेकिन वे चाहते हैं कि इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए और बिना सर्वदलीय सहमति के इसे जल्दबाजी में लागू न किया जाए।

संसद का आगामी मानसून सत्र २० जुलाई से शुरू होने जा रहा है, जिसमें कई अहम विधेयकों को पेश किए जाने की योजना है।